

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

प्रलिस के लिये:

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, एसडीजी, नीतियायोग

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने [आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#) को ब्लॉक और शहर के स्तर तक वसितारति करने की इच्छा व्यक्त की है।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:

परचिय:

- इसे जनवरी 2018 में 'आकांक्षी ज़िलों का परवित्तन' कार्यक्रम (Transformation of Aspirational Districts' Programme-TADP) के रूप में लॉन्च कया गया था।
- आकांक्षी ज़िले भारत के वे ज़िले हैं जो खराब सामाजकि-आर्थकि संकेतकों से परभावति हैं।

कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा:

- अभसिरण (केंद्र और राज्य की योजनाओं का)
- सहयोग (केंद्रीय, राज्य सूतरीय 'परभारी' अधिकारियाँ और ज़िला कलेक्टरों का),
- मासकि डेल्टा रैकगि के माध्यम से ज़िलों के बीच परतसिपर्द्धा।
 - आकांक्षी ज़िलों की डेल्टा रैकगि, व्यावहारकि परशासन के साथ डेटा के अभनिव उपयोग को जोड़ती है, जसिसे ज़िले को समावेशी वकिस के केंद्र में रखा जाता है।

उद्देश्य:

- यह परत्येक ज़िले की क्षमता पर ध्यान केंद्रति करता है, एवं तत्काल सुधार के लिये परभावी कारकों की पहचान करता है और मासकि आधार पर ज़िलों की रैकगि करके परगता को मापता है।
- ज़िलों को अपने राज्य में सबसे अचछे ज़िले के समान स्थिति में पहुँचने के लिये परोत्साहति कया जाता है और बाद में परतसिपर्द्धी तथा सहकारी संघवाद की भावना से दूसरों से परतसिपर्द्धा करके और दूसरों से सीखकर देश के सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिये प्रेरति कया जाता है।
- "सबका साथ, सबका वकिस और सबका वशिवास" (**Sabka Saath Sabka Vikas aur Sabka Vishwas**) के अपने नारे के साथ सरकार अपने नागरकिों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिये समावेशी वकिस सुनिश्चिति करने हेतु परतबिद्ध है।
- ADP अनविर्य रूप से सतत् वकिस लक्ष्यों को स्थानकि बनाने के उद्देश्य से है, जसिसे राष्ट्र की परगता सुनिश्चिति की जा सके।

रैकगि के लिये पैरामीटर:

- रैकगि 5 व्यापक सामाजकि-आर्थकि वषियों के तहत 49 परमुख परदर्शन संकेतक (KPIs) में की गई वृद्धशील परगता पर आधारति है -
 - स्वास्थ्य और पोषण (30%)
 - शकिषा (30%)
 - कृषि और जल संसाधन (20%)
 - वत्तितीय समावेशन और कौशल वकिस (10%)
 - अवसंरचना (10%)

वभिनिन कार्यक्रम:

- वभिनिन कार्यक्रम जैसे - सक्षम बटिया अभयान, [एनीमया मुक्त भारत](#) और [सुरक्षति हम सुरक्षति तुम](#), कुछ परमुख पहल हैं जो इस संबंध में [नीतियायोग](#) द्वारा शुरू की गई हैं।

ADP से जुड़ी चुनौतियाँ:

- अपर्याप्त बजटीय संसाधन:

- अपर्याप्त बजटीय संसाधनों से संबंधित मुद्दे से ADP प्रभावित होता है।
- **समन्वय की कमी:**
 - ADP को कई मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाता है जिससे समन्वय की कमी होती है।
- **डेटा उच्च गुणवत्ता वाला प्रशासनिक डेटा:**
 - स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन और डिज़ाइन में सुधार के लिये उच्च गुणवत्ता वाला प्रशासनिक डेटा महत्वपूर्ण है।
- **रैंकिंग वृद्धि:**
 - **डेल्टा रैंकिंग** स्वयं काफी हद तक गुणवत्ता के बजाय मात्रा (यानी, पहुँच का कवरेज) का आकलन करने पर केंद्रित है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता:**
 - इसके अलावा, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एक नरिशाजनक स्थिति में है, जैसा कि ASER रिपोर्ट द्वारा पता चलता है।

आगे की राह

- एक अधिक सरलीकृत सूचकांक की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न परिणाम संकेतकों को सावधानीपूर्वक चुना गया हो ताकि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके।
- स्थानीय प्रशासन को और अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिये।
- स्वतंत्र सर्वेक्षणों का उपयोग प्रशासनिक डेटा को मान्य करने के लिये किया जा सकता है, यह डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।
- प्रशासनिक डेटा में सुधार के लिये प्रत्येक ज़िले की आंतरिक क्षमता में बढोत्तरी की जानी चाहिये, और डेटा उपयोग की संस्कृति को बढावा देना, ADP के लिये प्राथमिकता बनाई जा सकती है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. अटल इनोवेशन मशिन कसि के अंतरगत स्थापति कयि गया है? (2019)

- वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- श्रम और रोज़गार मंत्रालय
- नीति आयोग
- कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय

- अटल इनोवेशन मशिन (AIM) देश की नवाचार और उद्यमशीलता की ज़रूरतों पर वसितृत अध्ययन और विचार-विमर्श के आधार पर नवाचार और उद्यमता को बढावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा स्थापति एक प्रमुख पहल है।
- AIM को व्यापक नवाचार संगठन के रूप में परकिलपति कयि गया है जो विभिन्न स्तरों पर नवाचार और उद्यमशीलता के पारस्थितिकी तंत्र की स्थापना और संवर्धन को प्रोत्साहति करने वाली केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के बीच नवाचार नीतियों के संरेखण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसे-उच्चतर माध्यमिक स्कूल, वजिज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्च शैक्षणिक संस्थान, SME/ MSME उद्योग, कॉर्पोरेट और गैर सरकारी संगठन के स्तर।

अतः विकल्प (c) सही है।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स